

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

- 3- अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
4- उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार।

आवास विभाग

देहरादून, दिनांक 18 मार्च 2008

विषय : उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1803/V-आ0-2005-187(आ0)/01टी0सी0-1 दिनांक 4-8-2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड नजूल नीति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-27 के अनुसार नजूल नीति निर्गत होने से दो वर्ष तक लागू रहने की व्यवस्था निर्धारित थी। उक्त नीति के लागू रहने की तिथि दिनांक 3-8-2007 को समाप्त हो गयी है।

2- तत्पश्चात् नजूल नीति लागू रहने की अवधि समाप्त होने के उपरांत शासनादेश सं0-CM-134/V-आ0-2005-187(आ0)/01टी0सी0-1 दिनांक 22-10-2007 द्वारा फीहोल्ड के ऐसे लम्बित प्रकरण, जिनमें स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि दिनांक 03-8-2007 तक राजकोष में जमा की जा चुकी है, में नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 4-8-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रतार कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये।

3- उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश सं0-1803/V-आ0-2005-187(आ0)/01टी0सी0-1 दिनांक 4-8-2005 के प्रस्तर 27 में संशोधन करते हुए निर्गत नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31-7-2008 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- उक्त के अतिरिक्त नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 4-8-2005 में अन्तर्निहित व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

5- कृपया नजूल भूमि फीहोल्ड के लम्बित प्रकरणों में उत्तराखण्ड नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 4-8-2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रतार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या 492(I) 187(आ0)/01टी0सी0-I तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

- 1- समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
2- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 पंत)
अनु सचिव